सेंसेक्स फिर हुआ बीस हजार के पार

मुंबई। कुछ विदेशी निवेश सीमा में ढील देने की सरकार की पहल और विदेशी निवेशकों की सतत लिवाली के बल पर बांबे स्टाक एक्सचेंज ने सेंसेक्स ने एक बार फिर 20,000 का स्तर हासिल कर लिया। तीस शेयरों वाला सेंसेक्स आज 184.17 अंक चढ़कर 20,045.18 अंक पर बंद हुआ। जनवरी, 2008 के बाद सेंसेक्स का यह उच्चतम स्तर है। उधर, नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 58.75 अंक की बढ़त के साथ 6,018.30 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 6,029.10 अंक के दिन के उच्च स्तर को छू गया था। ■

वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली में आयोजित कोयला सम्मेलन में कहा कि समस्या का निदान इसमें नहीं है कि कंपनियां खनन गतिविधियों को बंद कर दें।

वैभव बिजनेस

विराट वैभव नयी दिल्ली, शनिवार, 25 सितम्बर, 2010 15

भारत से जुड़े हैं यूएस के हित

तेजी से बढ़ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था

■ एजेंसी।

वॉशिंगटन। भारत ने अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में अमेरिकी कंपनियों के लिए संभावित अवसरों की ओर संकेत करते हुए संस्थान विदेशी संबंध परिषद सीएफआर द्वारा अयोजित एक परिचर्चा में कहा कि ओहियो राज्य द्वारा आउटसोर्सिंग पर प्रतिबंध जैसे किरकिरी पैदा करने वाले कदमों से बचा जा सकता। उम्मीद है कि ऐसी घटनाएं नहीं दिख रही हैं। शर्मा ने कहा कि दोनों देश रणनीतिक सहयोग कर रहे हैं और हमें केवल वही करना चाहिए जो इस सहयोग को मजबूत बनाए क्योंकि जब हम मिलकर काम करते हैं तो यहां परमाणु से अंतरिक्ष

अमेरिका की कुछ नीतियां संबंधों में पैदा कर रही हैं दरार

भारत अमेरिका के साथ चाहता है बेहतर संबंध

अमेरिका से कहा है कि वह विदेशों में काम करवाने पर पाबंदी जैसे संरक्षणादी अभियानों से बाज आए। भारत का मनना है कि विश्व की नंबर एक अर्थव्यवस्था अमेरिका में आउटसोर्सिंग आदि के खिलाफ अभियान संबंधों में किरकिरी बनते हैं। वाणिज्य उप उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने कल यहां शोध होंगी। भारत तथा अमेरिका परमाणु उर्जा क्षेत्र में व्यापार शुरू करने की ओर बढ़ रहे हैं। भारत ने 2020 तक अपनी परमाणु बिजली उत्पादन क्षमता 4,000 मेगावाट से बढा कर 20,000 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है। अमेरिकी परमाणु बिजलीघर विनिर्माता कंपनियों के लिए भारत में बड़ी संभावनाएं विज्ञान सहित बहुत कुछ दांव पर लगा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिका द्वारा वीजा फीस बढ़ाने तथा आउटसोर्सिंग पर प्रतिबंध जैसी घटनाएं सिर्फ कुछ समय तक के लिए ही होंगी। उन्होंने कहा कि इन्हें द्विपक्षीय सहयोग के व्यापक परिदृश्य के लिए सुलझा लिया जाना चाहिए।■

आईसीडब्लूएआई ने आईपीएआर के साथ किया करार

■ विराट न्यूज

नई दिल्ली। भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एवं वर्क्स एकाउंटस ऑफ इंडिया (आईसीडब्लूएआई) ने इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एकाउंट एवं ऑडिटर्स ऑफ रसिया के साथ एक ऐतिहासिक करार किया है। यह समझौता कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के भारतीय सचिव आर बंदोपाध्याय गुरुवार को मांस्को में किया। इस मौके पर आर बंधोपाध्याय ने कहा कि इससे दोनों देशों के एकाउंटिग क्षेत्रों को विचारों के आदान प्रदान करने में मदद मिलेगी। साथ ही यह समझौते दोनों देशों को जी-20 देशों से जोड़ने में सहायक होगा।

इसके बाद दोनों देश सहमति के साथ इस विषय पर अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में पहल करेंगे। इस समझौते पर आईसीडब्लूएआई की ओर से इसके अध्यक्ष बी एम शर्मा और आईपीएआर के अध्यक्ष वी वी सकोबारा ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर बी एम शर्मा ने कहा कि यह ऐतिहासिक करार व्यवसाय के क्षेत्रों में दोनों देशों को अच्छे संबंध बनाने में सहायक बनेगा। आईसीडब्लूएआई के अध्यक्ष बी एम शर्मा अभी रसिया के कार्यकारी दौरे पर गए हुए हैं। जहां उन्होंने रसिया के उप वित्त मंत्री सार्जे दिमित्रीविच सहित क ई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की। ■

एनएचपीसी ने किया 34 वीं आम बैठक का आयोजन

■ विराट न्यूज

नई दिल्ली। जल विद्युत क्षेत्र में मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त देश की अग्रणी कंपनी एनएचपीसी ने हाल ही में 34वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन फरीदाबाद में किया गया। एनएचपीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक एस के गर्ग ने कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों तथा विद्युत मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में शेयरधारकों को संबोधित किया। शेयर धारकों को संबोधित करते हुए गर्ग ने कहा कि कंपनी की सफलता के लिए मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। पुरानी उपलब्धियों को पीछे की बात बताते हुए उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी ने नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। इस वित्त वर्ष की समाप्ति पर गर्ग ने वार्षिक रिपोर्ट का बारे में बताते हुए कहा कि एनएचपीसी ने 4327 करोड़ रुपए का कारोबार करते हुए कंपनी ने 2090 का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। जो अब तक का सर्वाधिक है। कंपनी ने अविस्मरणीय तरक्की करते हुए यह मुकाम हासिल किया है। एनएचपीसी की सशक्त कार्य प्रणाली और लगन इस क्षेत्र में बेहतर लाभ का कारण बनीं हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष निदेशकों ने प्रति शेयर .55 रुपए का लाभांश देने की घोषणा की है। गर्ग ने कहा कि कंपनी आगे भी इसी तरह की बेहतर कार्यप्रणाली का हिस्सा बनेगी।■

भेल देगा 233 फीसदी लाभांश

■ विराट न्यूज

नई दिल्ली। भारतीय सहकारी उपक्रम भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (भेल) वित्त वर्ष 2009-2010 में 233 प्रतिशत लाभांश देगा। पिछले वर्ष कंपनी का यही लाभांश 170 फीसदी था। अब तक कंपनी ने सबसे अधिक 1,141 करोड़ का लाभांश दिया है। कंपनी ने पिछले

तीन दशकों के बिना किसी रुकावट के प्रति वर्ष अच्छे लाभ प्राप्त किए हैं। कंपनी ने लाभांस स्वरूप 408 करोड़ रुपए का एक चैक सरकार को सौंप दिया। चैक, केन्द्रीय भारी उद्योग मंत्री विलासराव देशमुख को भेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बी पी राव ने केन्द्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री अरुण यादव के उपस्थिति में सौंपा। इस अवसर पर भेल और भारी उद्योग मंत्रालय की कई हस्तियां मौजूद थीं। भेल ने वर्ष 2009-10 में अब तक सबसे अधिक 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की और कंपनी का कुल टर्नओवर 34,154 करोड़ पर पहुंच गया। भेल ने तिमाही में सबसे अधिक 37 फीसदी की बढ़त के साथ कुल 4.311 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा अर्जित किया। कंपनी के पास अभी कई करोड़ के टेंडर हैं ■

एक और छोटी कार लॉन्च करेगी होंडा

■ एजेंसी।

नई दिल्ली। जापान की बड़ी कार निर्माता कंपनी होंडा मोटर्स जल्द ही भारतीय कार बाजार में धूम मचाने की तैयारी में है। भारतीय बाजार में कंपनी अपनी एक और छोटी कार लांच करने वाली है। जनवरी में इस कार का ट्रायल प्रॉडक्शन शुरू हो जाएगा और अगस्त-सितंबर में यह कार बाजार में आ जाएगी। कंपनी ने दावा है कि या है कि यह कार प्रति लीटर 22 किलोमीटर तक माइलेज दे देगी। कंपनी ने इसकी कीमत साढ़े चार लाख रुपए तक रहने की उम्मीद जताई है। इस कार पर होंडा की निगाहें टिकी हुई है क्योंकि देश में अब छोटी कारों का ही बोलबाला दिखाई दे रहा है। होंडा की पिछली छोटी कार जैज बाजार में खास हलचल नहीं मचा पाई थी। जानकारों का मानना है कि ज्यादा कीमत के चतले लोगों ने इसे खास पसंद नहीं किया। यही वजह है कि अब होंडा मोटर्स कम कीमत वाली छोटी कार लांच करने की तैयारी में है। छोटी कारों के बाजार में स्पर्धा बढ़ती ही जा रही है। जर्मन कंपनी फॉक्सवागेन भी भारत में एक और सस्ती छोटी कार लांच करने की तैयारी में है। इसके लिए वह मारुति सुजूकी से हाथ मिला सकती है। बड़ी कार बनाने वाली कई कंपनियां इस समय छोटी कारें बनाने पर जोर दे रही हैं। ■

आरईसी ने घोषित किया 65 फीसदी लाभांश

■ विराट न्यूज

नई दिल्ली। नए वित्त वर्ष में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपने निवेशकों को 65 फीसदी लाभांश देने की घोषणा की है। नवरत्न से सम्मानित कंपनी के मुख्य प्रबंध निदेशक जे एम पाठक ने गुरुवार को 230.86 करोड़ रुपए का चैक केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे को सौपा। इस अवसर पर ऊर्जा सचिव पी उमाशंकर और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। इस साल कंपनी को 210.76 के अंतरिम लाभांस सहित कुल 441.62 करोड़ का लाभ प्राप्त हुआ है। आरईसी ने अपने निवेशकों को प्रति शेयर 6.50 शेयर देने की पेशकश की है। कंपनी की यही ग्रोथ वित्त वर्ष 2010-11 में भी जारी है। इसी सफलता के मद्देनजर कंपनी ने ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक करार भी किया है। कंपनी को पिछले वर्ष एक्सीलेंट कंपनी के अवार्ड से नवाजा गया था।■

निवेशक गिने चुने लोगों के लिए काम करना बंद करें

■ एजेंसी

मुंबई। शेयर बाजार में बढ़ती तेजी को देखते हुए बाजार नियामक सेबी ने विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई)से कहा है कि वह कुछ गिने चुने व्यक्तियों से धन लेकर उसे पूंजी बाजार में लगाने से बाज आएं। यह नया नियम एक अक्टूबर से लागू होना है। सेबी अध्यक्ष सी.बी. भावे ने नए नियम को अमल में लाने की अंतिम तिथि को एक अक्टूबर से आगे बढ़ाने की विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि एफआईआई को नए नियम के अनुरूप उपयुक्त ढांचे के तहत नए सिरे से पंजीकरण कराना होगा। नए नियमों के अनुसार एफआईआई और उनके प्रत्येक उपखाते में 20 से कम निवेशक नहीं होने चाहिए, हालांकि इसमें कुछ इकाइयों जैसे पेंशन कोष को इस शर्त से अलग रखा गया है। पिछले दिनों शेयर बाजार में इस बात को लेकर चिंता जताई गई थी कि अकूत संपत्ति वाले कुछ लोग एफआईआई का इस्तेमाल करते हुए पूंजी बाजार में पैसा लगा रहे हैं। सेबी के नए नियमों में यह भी शर्त रखी गई है कि निवेश के लिए जुटाई गई राशि में किसी एक निवेशक की 49 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। भावे ने एक कार्यक्रम के मौके पर यहां संवाददाताओं से कहा कि विदेशी संस्थागत निवेशकों को एक अक्टूबर की समयसीमा के अनुरूप काम करना होगा। शेयर बाजार में एफआईआई के जरिए भारी पूंजी प्रवाह के बारे में पूछे जाने पर भावे ने कहा कि फिलहाल घरेलू बाजार में पूंजी प्रवाह को लेकर हमें कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि बाजार में आई तेजी से फिलहाल सौदों के निपटान से जुड़ी कोई समस्या सामने नहीं आई है और नियामक बाजार पर लगातार नजरें गड़ाए हुए है। कंपनियों के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) आने के बाद वर्तमान 20 दिन के बजाय मात्र सात दिन में बाजार में उसे सूचीबद्ध कराने की नई व्यवस्था के बारे में पूछे जाने पर भावे ने कहा यह अनिवार्य नहीं है बल्कि एक विचार है । हमारा पैनल इसकी व्यवहार्यता को देख रहा है, पैनल नवंबर तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगा उसके बाद हम इसपर अंतिम निर्णय लेंगे। ■

रिलायंस गैस भंडारों में तकनीकी खामियां

डीजीएस ने किया चौंकाने वाली घटना का खुलासा

■ एजेंसी

नई दिल्ली। हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) ने चौंकाने वाली कारवाई करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के कृष्णा गोदावरी बेसिन क्षेत्र के एक अन्य कुएं में हुई गैस का बड़ा भंडार मिलने के दावे को खारिज कर दिया है। तेल खोज और खनन क्षेत्र के विनियामक ने कहा है कि मुकेश अंबानी की इस कंपनी ने भंडार की पुष्टि के लिए आवश्यक जांच से पहले उसे नोटिस नहीं दिया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज को पिछले महीने केजी बेसिन के केजी (डीडब्ल्यूएन-2003-1) ब्लॉक के चौथे कुएं में गैस का पता चला है। यह क्षेत्र कंपनी के केजी बेसिन स्थित बहुचर्चित डी-छह ब्लॉक के पास ही है। सूत्रों के अनुसार केजी (वी-डी3-डब्ल्यूएक) में गैस खोज की पुष्टि उपयुक्त परीक्षण और डाटा जुटाने के साथ की गई थी और पूरी रिपोर्ट डीजीएच को सौंप दी गई थी। लेकिन इस मामले में परीक्षण से पहले कंपनी डीजीएच को 48 घंटे का नोटिस देने में चूक कर गई। डीजीएच ने एक सितंबर को रिलायंस इंडस्ट्रीज को लिखा कि नई खोज को देखने के लिए ऑपरेटर (रिलायंस) ने डीजीएच को कोई नोटिस जारी नहीं किया। यह उत्पादन भागीदारी अनुबंध के अनुच्छेद 10.2 का उल्लंघन है। डीजीएच ने कंपनी को लिखा है कि अनुबंध के अनुच्छेद 10.2 के उल्लंघन को देखते हुए उस ब्लॉक में अधिसूचित गैस खोज जिसका नाम धीरुभाई 52 रखा गया है को गैस खोज नहीं माना जाएगा। उत्पादन भागीदारी अनुबंध के तहत डीजीएच को गैस खोज को स्वंय देखने के लिए अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया है। हालांकि, उद्योग जगत ने डीजीएच के इस कदम को हैरानी भरा बताया हैं। उद्योगजगत का मानना है कि जिस देश में तेल एवं गैस आपूर्ति के लिए आयात पर भारी निर्भरता हो वहां तेल एवं गैस खोज का स्वागत किया जाना चाहिए लेकिन डीजीएच ने एक प्रक्रियागत कमी के चलते पूरी खोज को ही नामंजूर कर दिया यह चौकाने वाला कदम है। उद्योग जगत सूत्रों ने कहा कि डीजीएच को पूरी खोज को ही खारिज करने के बजाय कंपनी को उसकी कमी पर चेतावनी देनी चाहिए थी अथवा दूसरा परीक्षण करने के लिए कहना चाहिए था। बहरहाल, रिलायंस प्रवक्ता से तुरंत इस मुद्दे पर संपर्क नहीं हो पाया। रिलायंस को (केजी-डी3-डब्ल्यूएक) में गहरे समुद्र में डी3 नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र में समूद्रतल से 3,501 मीटर नीचे प्राकृतिक गैस का पता चला था। ब्लॉक में यह लगातार चौथी गैस खोज थी। क्षेत्र में रिलायंस 90 प्रतिशत हिस्से के साथ ऑपरेटर है जबकि शेष 10 प्रतिशत हिस्सेदारी ब्रिटेन की हार्डी ऑयल के पास है। रिलायंस को यह ब्लॉक नेल्प के पहले दौर में वर्ष 2000 में मिला था।■

कोका कोला कंपनी के उपाध्यक्ष दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के साथ मिलकर राष्ट्रमंडल खेलों के लिए पेय पदार्थ का शुभारंभ करते हुए । फोटोः वैभव